प्रेस विज्ञप्ति

आठवीं ऐनुअल स्टेटस आफ़ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर 2012) जारी

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

ऐनुअल स्टेटस आफ़ एज्युकेशन रिपोर्ट, असर - 2012 आज नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन मंत्री डॉ एम.एम. पल्लम राजू द्वारा जारी की गई । यह आठवीं वार्षिक रिपोर्ट है ।

असर ग्रामीण भारत में बच्चों का सबसे बड़ा वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण है जो कि स्कूली शिक्षण स्थिति और बुनियादी अधिगम स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है । प्रथम की मदद से, असर हर ग्रामीण ज़िले में स्थानीय संगठनों, संस्थाओं और चिंताशील नागरिकों द्वारा किया जाता है । असर 2012 में 567 ज़िलों, 16000 से अधिक गाँवों, करीबन 3.3 लाख से अधिक परिवारों और 3-16 वर्ष के लगभग 6 लाख बच्चों तक पहुँचा ।

हर वर्ष, असर पता करता है कि क्या ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल जाते हैं और क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और बुनियादी गणित कर सकते हैं | 2009 से, असर में हर सैम्पल किए गए गाँव में एक सरकारी स्कूल का अवलोकन भी शामिल किया गया है । 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) लागू होने के बाद से, असर में किए गए स्कूलों के अवलोकन में शिक्षा के अधिकार में निर्दिष्ट ऐसे मानकों और मानदंडों के अनुपालन से सम्बंधित संकेतकों को भी शामिल किया गया है जो कि आसानी से मापे जा सकते हैं । 2012 में, असर में लगभग 14,600 सरकारी स्कूलों का अवलोकन किया गया ।

असर 2012 - प्रमुख निष्कर्ष

कुल मिलाकर, 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन दर 96% से अधिक बने हुए हैं । करीब करीब सभी राज्यों में निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है ।

ग्रामीण भारत में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन दर उच्च बने हुए हैं । 2012 में, ग्रामीण भारत में इस आयु वर्ग के 96.5% से भी अधिक बच्चे स्कूलों में नामांकित थे । यह लगातार चौथा वर्ष है, जब नामांकन दर 96% या उससे अधिक रहे हैं ।

राष्ट्रीय स्तर पर, 6-14 आयु वर्ग में उन बच्चों का अनुपात जो किसी स्कूल में नामांकित नहीं हैं कुछ बढ़ा है । जहाँ 2011 में यह 3.3 प्रतिशत था, 2012 में यह कुछ बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गया है । यह बढोतरी 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाधिक है, इस वर्ग के लिए अनामांकित बच्चों का प्रतिशत 2011 में 5.2 से बढ़कर 2012 में 6 हो गया है । राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का प्रतिशत जो स्कूल में नामांकित नहीं थीं, 2011 में क्रमशः 8.9% और 9.7% से बढ़कर 2012 में 11% से भी अधिक हो गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर, 6-14 आयु वर्ग के लिए निजी स्कूलों में नामांकन साल दर साल बढ़ा है, 2006 में 18.7% से बढ़कर 2012 में 28.3% हो गया है । पिछले तीन वर्षों में, निजी स्कूलों में नामांकन में

बढ़ोतरी का दर लगभग 10 प्रतिशत प्रति वर्ष रहा है और यदि यह दर बना रहा तो, 2018 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे होंगे ।

निजी स्कूलों में नामांकन में बढ़ोतरी करीब-करीब सभी राज्यों में देखने को मिल रही है । 2012 में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और मेघालय में आयु वर्ग 6-14 के 40% से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे । केरल और मणिपुर के लिए यह प्रतिशत 60 या अधिक था ।

ग्रामीण भारत में, प्रारंभिक स्तर पर यानी कक्षा 1-8 के करीब एक चौथाई बच्चे, चाहे वे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हों या फिर सरकारी स्कूलों में, पैसे देकर निजी ट्यूशन के लिए जाते हैं । सामान्यतः, जो बच्चे यह अतिरिकित शिक्षण सहायता प्राप्त करते हैं उनके शिक्षण स्तर उन बच्चों की तुलना में बेहतर हैं जो इसे प्राप्त नहीं करते । 2012 में, कक्षा 1-8 में नामांकित बच्चों में करीबन 45% बच्चे निजी स्कूल और/या निजी ट्यूशन जा रहे थे ।

बुनियादी पाठ पढ़ने और गणित करने के कौशल अत्यधिक चिंता का कारण बने हुए हैं |

2010 में राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा 5 के आधे से अधिक (53.7%) बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम थे । यह अनुपात गिरकर 2011 में 48.2% तथा 2012 में और गिरकर 46.8% हो गया है । बुनियादी पढ़ने के स्तरों में गिरावट, निजी स्कूलों में जा रहे बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों में जा रहे बच्चों में अधिक देखने को मिल रही है । सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के बच्चों में उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2010 में 50.7% से गिरकर 2012 में 41.7% हो गया है ।

2011 और 2012 के बीच, कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में पढ़ने के स्तर में बड़ी गिरावट (5% बिंदु या अधिक) देखी गई । महाराष्ट्र और केरल में तो निजी स्कूल भी, जिनमें बड़े अनुपात में सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल भी शामिल हैं, कक्षा 5 में पढ़ने की क्षमता में गिरावट दिखा रहे हैं ।

2012 को भारत में गणित के वर्ष के रूप में मनाया गया | परन्तु भारतीय बच्चों के लिए बुनियादी गणित के मान से यह वर्ष खराब रहा । 2010 में, 10 में से 7 (70.9%) कक्षा 5 में नामांकित बच्चे दो अंकों का घटाव (जिसमें हासिल लेना पड़ता हो) कर सकते थे | 2011 में यह अनुपात घटकर 10 में से 6 (61%) और 2012 में और गिरकर 10 में से 5 (53.5%) हो गया है । आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को छोड़कर, हर बड़ा राज्य गणित के स्तरों में भारी गिरावट के संकेत दिखा रहा है ।

2011 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों और 2012 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना करें तो, लगभग सभी राज्यों में बुनियादी घटाव करने की क्षमता में 10 प्रतिशत बिंदु से अधिक की गिरावट देखी जा सकती है । इसमें अपवाद हैं बिहार, असम और तमिलनाडु जहाँ यह गिरावट कम है; तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रदेश जहाँ या तो 2011 की तुलना में सुधार हुआ है या कोई खास बदलाव नहीं हुआ है |

स्कूलों के अवलोकन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

भारत में छोटे स्कूलों का अनुपात बढ़ रहा है। असर 2012 के दौरान, कुल 14,591 स्कूलों का अवलोकन किया गया। समय के साथ, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 60 या उससे कम नामांकन वाले सरकारी प्राथमिक स्कूलों का अनुपात बढ़ा है, 2009 में 26.1% से बढ़कर 2012 में 32.1% हो गया है |

प्राथमिक कक्षाओं में उन बच्चों का अनुपात भी बढ़ रहा है जो मल्टिग्रेड कक्षाओं में बैठते हैं । कक्षा 2 के लिए, यह प्रतिशत 2009 में 55.8% से बढ़कर 2012 में 62.6% हो गया है | कक्षा 4 के लिए, यह प्रतिशत 2010 में 51% से बढ़कर 2012 में 56.6% हो गया है |

शिक्षा के अधिकार (RTE) के मानकों के आधार पर, छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) में समय के साथ सुधार दिख रहा है | 2010 में, उन स्कूलों का अनुपात जो छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों को पूरा कर रहे थे 38.9% था | 2012 में यह बढ़कर 42.8% हो गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूलों की सुविधाओं में भी समय के साथ सुधार दिख रहा है । स्कूलों में बुनियादी सुविधाओ की उपलब्धता में सुधार स्पष्ट दिख रहा है: 2012 में, अवलोकन किए गए सभी स्कूलों में 73% स्कूलों में पेयजल उपलब्ध था | उन विद्यालयों का अनुपात जिनमें उपयोग करने योग्य शौचालय है 2010 में 47.2% से बढ़कर 2012 में 56.5% हो गया है । अवलोकन किए गए स्कूलों में लगभग 80% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान था | अवलोकन किए गए स्कूलों में 87.1% स्कूलों में सर्वे के दिन देखा गया कि मध्याह्न भोजन दिया गया था |

2010 के कुछ साल पहले तक, शिक्षण स्तर निचले थे पर स्थिर बने हुए थे । परन्तु देशभर में, उसके बाद से बच्चों के साधारण पाठ पढ़ने और सामान्य गणित करने की क्षमता में गिरावट हुई है। हालांकि 2010 से शिक्षा के अधिकार में निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों के अनुपालन में सुधार हुआ है लेकिन आज स्कूलों में अधिकांश बच्चे, उन्हें जिस कक्षा-स्तर पर होना चाहिए, उससे तीन कक्षा-स्तर पीछे हैं । प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण स्तर में कमियाँ माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण स्तरों को भी प्रभावित करती हैं ।

12वीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों में "सभी कक्षाओं में बेहतर शिक्षण स्तर, जिसमें कक्षा 2 तक बुनियादी पढ़ने और अंकगणित करने के कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान" शामिल है । 12वीं पंच वर्षीय योजना के मध्य नज़र यह आवश्यक है कि 2013-14 शिक्षण सत्र के लिए चरणबद्ध लक्ष्य तुरंत तय किए जाएँ । सभी व्यवस्था - शिक्षकों का प्रशिक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को गठबंधित होना होगा जिससे स्कूलों को यह लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिले । आने वाले शैक्षणिक सत्र में सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए जा रही योजनाओं में इन शिक्षण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस और लागू करने योग्य लक्ष्य और उपाय दिखाई देने चाहिए।

संतोषजनक शिक्षण स्तर सुनिश्चित किए बिना शिक्षा की गारंटी अर्थहीन है । यदि बुनियादी शिक्षण स्तरों में जल्द ही सुधार न हुआ तो इसके देश में समानता और विकास पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं ।